भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
24.07.2024 के
तारांकित प्रश्न सं. 33 का उत्तर

तमिलनाडु में रेल परियोजनाएं

***33. श्री जी. सेल्वम:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में किन्हीं ऐसी रेल परियोजनाओं की पहचान की है जो वर्तमान में निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु में रेल परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट कदम उठाए हैं;
(घ) क्या सरकार की राज्य भर में कनेक्टिविटी और प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार लाने के लिए लंबित परियोजनाओं को आरम्भ करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

s.k

तमिलनाडु में रेल परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 24.07.2024 को लोक सभा में श्री जी. सेल्वम के तारांकित प्रश्न सं. 33 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): रेल परियोजनाएं राज्य-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत की जाती हैं क्योंकि भारतीय रेल परियोजनाएं विभिन्न राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली 33,467 करोड़ रु. लागत वाली 2,587 कि.मी. लंबाई की 22 रेल परियोजनाएं (10 नई लाइन, 03 आमान परिवर्तन और 09 दोहरीकरण) योजना/स्वीकृति/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 665 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक 7,153 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। इनमें शामिल हैं :-

- **14,669 करोड़ रु. लागत वाली 872 कि.मी. कुल लंबाई की 10 नई लाइन परियोजनाएं, जिनमें से 24 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक 1,223 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।**

- **5,417 करोड़ रु. लागत वाली 748 कि.मी. कुल लंबाई की 03 आमान परिवर्तन परियोजनाएं, जिनमें से 604 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक 3,267 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।**

- **13,381 करोड़ रु. लागत वाली 967 कि.मी. कुल लंबाई की 09 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिनमें से 37 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक 2,664 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।**

तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली रेल परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत आती हैं। नवीनतम स्वीकृत लागत, व्यय और परिव्यय सहित सभी रेल परियोजनाओं का जोन-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

s.k

रेलवे द्वारा रेल परियोजनाओं को लक्ष्यबद्ध समय-सीमा में पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाते हैं। रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं।

इनमें शामिल हैं:- (i) गति शक्ति इकाइयां स्थापित करना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण करना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर निधि के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करना (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन करना (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना।

वर्ष 2014 से परियोजनाओं के लिए बजट आबंटन और तदनुरूपी कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना और संरक्षा परियोजनाओं के लिए बजट आबंटन बढ़ाकर 6,362 करोड़ रु. कर दिया गया है, जो 2013-14 में 922 करोड़ रु. के बजट आबंटन का लगभग सात गुना है।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना और संरक्षा कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	औसत परिव्यय	वर्ष 2009-14 के औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	879 करोड़ रु. प्रति वर्ष	-
2023-24	6,080 करोड़ रु.	लगभग 7 गुना

s.k

2014-24 में तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाले 1302 कि.मी. रेलखंड (39 कि.मी. नई लाइन, 456 कि.मी. आमान परिवर्तन और 807 कि.मी. दोहरीकरण) को 130.2 किलोमीटर प्रति वर्ष की औसत दर पर कमीशन किया गया है।

यद्यपि निधि आबंटन में कई गुना वृद्धि हुई है, परन्तु परियोजना के निष्पादन की गति शीघ्र भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करती है। रेलवे भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार के माध्यम से करती है। राज्य सरकार मुआवजे की राशि का आकलन करती है और रेलवे को सूचित करती है। राज्य सरकार से मांग प्राप्त होने पर, रेलवे संबंधित जिला भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के पास मुआवजे की राशि जमा करा देती है। तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है और लगभग 2749 हेक्टेयर भूमि की कुल आवश्यकता में से केवल लगभग 807 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। रेलवे ने भूमि अधिग्रहण के लिए प्रयास शुरू किए थे, परन्तु परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सफल नहीं हो सकी। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए तमिलनाडु सरकार के समर्थन की आवश्यकता है।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली निम्नलिखित परियोजनाओं का निष्पादन मुख्यतः तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा भूमि सौंपने में विलंब के कारण लंबित है :-

क्र.सं.	परियोजनाओं के नाम	लंबाई
1.	तिरुवनंतपुरम - कन्याकुमारी दोहरीकरण	87 किलोमीटर
2.	टिंडीवनम - नागरी नई लाइन	184 किलोमीटर
3.	मोरप्पुर - धर्मपुरी नई लाइन	36 किलोमीटर

s.k

किसी भी रेल परियोजना(ओं) का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, लागत में साझेदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा साझा लागत के भाग को जमा कराना, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक क्लीयरेंस, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना(ओं) स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति, आदि के कारण परियोजना विशेष के स्थल के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना(ओं) के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अतः इस स्तर पर परियोजना(ओं) के पूरा होने की कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

*****